UNIVERSITY NEWS 11 FEBRUARY 2026

TIMES OF INDIA

For no additional fee, LU proposes to centralise college admissions

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: Lucknow University has proposed its affiliated govt and aided colleges to be part of centralised admission process in which it will not charge any additional fee. It was also proposed to convert girls' degree colleges struggling to fill undergraduate and postgraduate seats to be converted into co- educational institutions. The proposal was made during a meeting of LU vice-chancellor Prof J P Saini with principals of affiliated colleges on Tuesday. The meeting aimed to strengthen academic, administrative and research collaboration between the university and colleges. During the meeting, it was decided that colleges will be prepared for highest degree of autonomy in accordance with National Education Policy 2020. Teachers will be invited to workshops to encourage them to adopt curriculum-conscious, student-friendly pedagogy.

"University has proposed admissions for aided colleges and govt colleges to be integrated with the university's process. Due to limited seats on university campus, a large number of students are unable to secure admission, so they would be given opportunities in affilliated and aided colleges," said Prof Mukul Srivastava, LU spokesperson.

He said that as per arrangement, university would not charge additional fees and colleges would conduct the admission process on their own and Vice-Chancellor Saini had given principals 10 days to consider the process.

Another decision taken was that college departments would be recognised as research centres, providing departments with full support from the university and provide new direction for research work. A committee formed by the university will oversee the establishment of research centers. Saini clarified communication between university and colleges would remain active and he would meet college principals every six months.

The concern of undergraduate and postgraduate seats in colleges falling vacant was also discussed during the meeting. It was stated that girls' colleges in particular were experiencing a decline in number of female students. It was suggested that such colleges be converted to co-education to provide more opportunities for female students.

Meanwhile, it was announced that LU's ranking cell will organise joint workshops with aided and govt colleges to prepare for NAAC and NIRF rankings. The workshops will provide guidance to colleges on quality standards, evaluation processes and ranking requirements. Additionally, the university will ensure that all colleges present their academic achievements, research work and student-friendly activities in accordance with the ranking standards.

VC Saini advises surprise checks

Lucknow University Vice Chancellor Prof J P Saini said teachers should not consider themselves superiors, but act as motivators and guides among students, as their cadre was distinct and they were guides of society. He emphasised that teachers should exercise influence on students and surprise inspections of classrooms be ensured to maintain quality of education.

AMRIT VICHAR

लविवि और महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया होगी एकरूप

कुलपति ने कहा, महाविद्यालय दुखी होंगे तो विश्वविद्यालय सुखी नहीं रह सकता, कुलपति छह माह में प्राचार्यों के साथ करेंगे बैठक

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति प्रो. जेपी सैनी महाविद्यालय प्रचार्यों के साथ बैठक करते हुए। अमृत विचार

अमृत विचार : लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया को एकरूप करने की दिशा में आम पहल की गई है। मंगलवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने एडेड एवं राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक कर प्रस्ताव दिया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया एक साथ संचालित की जाए, जिससे महाविद्यालयों की सीटें खाली न रहें।

बैठक में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के बीच शैक्षणिक, प्रशासनिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में सीमित सीटों के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता, ऐसे में उन्हें एडेड कॉलेजों में अवसर दिया जाएगा। इस व्यवस्था में विश्वविद्यालय कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा और महाविद्यालय अपने स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित करेंगे।

कुलपति ने यह भी घोषणा की कि महाविद्यालयों के विभागों को शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे विभागों को विश्वविद्यालय का पूर्ण सहयोग मिलेगा और शोध गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। शोध केंद्रों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति निरीक्षण करेगी।

बैठक में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी, वित्त अधिकारी हिमानी चौधरी और प्रवेश समन्वयक प्रो. अनिल गौरव उपस्थित रहे। संचालन क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. अश्विनी कुमार मिश्रा ने किया। बैठक के बाद प्राचार्यों ने कुलपति के प्रस्तावों का समर्थन किया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का संबंध कारपोरेट मॉडल की तरह होगा, जहां विश्वविद्यालय समस्याओं के समाधान में सहयोग करेगा।

संयुक्त कार्यशालाओं का होगा आयोजन

- नैक और रलआईआरएफ रैंकिंग को ध्यान में रखते हुए एडेड और राजकीय महाविद्यालयों के साथ संयुक्त कार्यशालाओं के आयोजन का निर्णय लिया गया। इन कार्यशालाओं में गुणवत्ता मानकों, मूल्यांकन प्रक्रिया और रैंकिंग से जुड़ी आवश्यकताओं पर महाविद्यालयों को मार्गदर्शन दिया जाएगा।

• महाविद्यालयों के विभागों को शोध केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा

• कन्या महाविद्यालयों में शुरू हो सकता है कोएजुकेशन

कोएजुकेशन को मिलेगा बढ़ावा

- बैठक में यह भी सामने आया कि महाविद्यालयों, विशेषकर कन्या महाविद्यालयों में छात्र संख्या लगातार घट रही है। इस पर विचार करते हुए कन्या महाविद्यालयों को सहशिक्षा में परिवर्तित करने का सुझाव दिया गया, ताकि छात्रों को अधिक अवसर मिल सकें। कुलपति ने विश्वास दिलाया कि प्रवेश उन्हाई के ये स्तर को अधिकारी नहीं बल्कि छात्रों का मार्गदर्शक और प्रेरक समझे। उन्होंने कक्षाओं के अधिक नियमित रूप से लेने पर बल दिया।

महाविद्यालय दुखी तो विवि सुखी नहीं रहेगा

- कुलपति ने कहा कि महाविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्चतम स्वायत्तता के लिए तैयार किया जाएगा। शिक्षकों को कार्यशालाओं के माध्यम से जागरूक, गतिशील और छात्र-हितैषी शिक्षण पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रवेश छह माह में महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ गंभीर बैठक की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि महाविद्यालय दुखी होगा तो विश्वविद्यालय सुखी नहीं रह सकता।

HINDUSTAN

एलयू प्रवेशप्रक्रिया से निशुल्क जुड़ेंगे एडेड, राजकीय कॉलेज

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय की केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया से अब एडेड व राजकीय कॉलेजों को निशुल्क जोड़ा जाएगा। जबकि अभी तक कॉलेजों से अलग-अलग पाठ्यक्रमों के अनुसार 50 हजार से एक लाख रुपये तक लिए जाते थे। यह निर्णय कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी की अध्यक्षता में राजकीय व एडेड कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक में लिया गया।

कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने बताया कि बैठक में प्रस्ताव रखा कि एडेड कॉलेजों और राजकीय महाविद्यालयों के प्रवेश विधि की प्रक्रिया से जोड़े जाएं। विश्वविद्यालय परिसर में सीमित सीटों के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता। ऐसे छात्रों को एडेड कॉलेजों में अवसर दिया जाएगा। इस व्यवस्था में विश्वविद्यालय कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लेगा और कॉलेज अपने स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित करेंगे। कुलपति ने इस प्रक्रिया के चिंतन के लिए प्राचार्यों को 10 दिन का समय दिया है। वहीं, प्राचार्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा कोई शुल्क न लेने के निर्णय की सराहना भी की।

साथ ही कुलपति ने घोषणा की कि महाविद्यालयों के विभागों को रिसर्च सेंटर के रूप में मान्यता दी जाएगी। इससे विभागों को विश्वविद्यालय से पूर्ण सहयोग मिलेगा और शोध कार्य को नई दिशा मिलेगी। शोध केंद्रों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति निरीक्षण करेगी।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्चतम स्वायत्तता के लिए तैयार किया जाएगा। शिक्षकों को कार्यशालाओं में आमंत्रित कर उन्हें जागरूक पाठ्यक्रम और छात्र-हितैषी शिक्षा पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कुलपति ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के बीच संवाद का माध्यम लगातार सक्रिय रहेगा। हर 6 महीने में कुलपति महाविद्यालयों के प्राचार्यों से बैठक करेंगे। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कई महाविद्यालयों में छात्र संख्या घट रही है। विशेषकर कन्या महाविद्यालयों में छात्राओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। सुझाव दिया गया कि ऐसे महाविद्यालयों को सह-शिक्षा में परिवर्तित किया जाए ताकि छात्राओं को अधिक अवसर मिल सके। कुलपति ने कहा कि शिक्षक स्वयं को अधिकारी न समझें, बल्कि छात्रों के बीच प्रेरक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं क्योंकि उनका संवर्ग एक अलग संवर्ग है जो समाज को राह दिखाता है।

बैठक में उपस्थित सभी प्राचार्यों ने इस पहल का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय के साथ सतत सहयोग करते रहेंगे। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का संबंध कॉर्पोरेट स्टाइल में होगा, जहां समस्याओं का स्पष्ट समाधान विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। इस बैठक ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के बीच सहयोग की नई राह खोली है।

50 हजार से एक लाख तक पाठ्यक्रमों के अनुसार लिए जाते थे

कॉर्पोरेट की तरह होगा विवि-कॉलेज संबंध

कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों का संबंध कॉर्पोरेट स्टाइल में होगा, जहां समस्याओं का स्पष्ट समाधान विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। शिक्षक स्वयं को अधिकारी न समझें, बल्कि छात्रों के बीच प्रेरक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं। शिक्षकों का प्रभाव छात्रों के बीच रहना चाहिए और औचक निरीक्षण करें।

अहम फैसले

1. कुलपति हर छह महीने पर कॉलेजों प्राचार्यों के साथ बैठक करेंगे
2. महिला कॉलेजों में छात्राओं की कमी, स्क-शिक्षा में बदलने का सुझाव।
3. कॉलेजों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्चतम स्वायत्तता के लिए तैयार किया जाएगा।
4. कॉलेज के विभागों को रिसर्च सेंटर के रूप में मान्यता दी जाएगी। निरीक्षण विधि की गठित समिति करेगी।

DAINIK JAGRAN

प्रवेश प्रक्रिया के लिए एडेड व राजकीय कालेजों को अब नहीं देना होगा शुल्क

कालेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक में कुलपति ने दी जानकारी

जागरण संवाददाता • लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ने वाले किसी भी राजकीय व एडेड डिग्री कालेजों को अब कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। कालेज अपने स्तर पर भी प्रवेश प्रक्रिया संचालित कर सकेंगे। मंगलवार को राजकीय व एडेड डिग्री कालेजों के साथ हुई बैठक में कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी ने यह प्रस्ताव रखा, जिसको वहां मौजूद सभी प्राचार्यों ने सराहा। इस व्यवस्था से हर साल प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ने वाले कालेजों को हजारों रुपये की बचत होगी।

दरअसल, पूर्व कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने लवि की संयुक्त प्रवेश प्रक्रिया में कालेजों को जोड़ने के लिए शुल्क निर्धारित किया था। हर पाठ्यक्रम के लिए करीब 50 हजार रुपये प्लस जीएसटी के साथ कालेज को जमा करना होता था, जिसके बाद काउंसिलिंग के आधार पर संबंधित कालेज में विद्यार्थी आवंटित किए जाते थे। मंगलवार को बैठक में कुलपति ने प्रस्ताव रखा कि एडेड कालेजों एवं राजकीय महाविद्यालयों के प्रवेश विश्वविद्यालय की प्रक्रिया से जोड़े जाएं। विश्वविद्यालय में सीमित सीटों के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता। ऐसे छात्रों को एडेड कालेजों में अवसर दिया जाएगा। इस व्यवस्था में विश्वविद्यालय कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा और कालेज अपने स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित करेंगे। इस प्रक्रिया के चिंतन के लिए प्राचार्यों को दस दिन का समय दिया है। बैठक में कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी, वित्त अधिकारी हिमानी चौधरी और प्रवेश समन्वयक प्रो. अनिल गौरव, उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. अश्विनी रहे।

कुलपति प्रो. जेपी सैनी के साथ बैठक में राजकीय व एडेड कालेजों के प्राचार्य • सौ सांवी

कम छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों में सह शिक्षा

कई कालेजों में घटती छात्र संख्या पर चिंता जताई गई। कन्या महाविद्यालयों में छात्राओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। सुझाव दिया गया कि ऐसे कालेजों को सह-शिक्षा में परिवर्तित किया जाए ताकि छात्राओं को अधिक अवसर मिल सकें।

तय हुआ कि पाठ्यक्रम में विशेषज्ञों के साथ कालेजों के शिक्षकों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। लवि की रैंकिंग सेल नैक और एनआइआरएफ की तैयारी के लिए एडेड व राजकीय कालेजों के साथ कार्यशालाएं कर मार्गदर्शन करेगी।

अवसर दिया जाएगा

इस व्यवस्था में विश्वविद्यालय कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा। कुलपति ने इस प्रक्रिया के चिंतन के लिए प्राचार्यों को दस दिन का समय दिया है।

कालेजों में होगी शोध केंद्रों की स्थापना

: कुलपति ने कहा कि दिग्गज कालेजों के विभागों को शोध केंद्र के रूप में मान्यता दी जाएगी। इससे विभागों को विवि से पूर्ण सहयोग मिलेगा और शोध कार्य को नई दिशा मिलेगी। शोध केंद्रों की स्थापना के लिए प्रेरित किया जाएगा। कुलपति ने स्पष्ट किया कि हर छह महीने में कुलपति कालेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक करेंगे।

INEXT

सोसायटी से बढ़ाएं तालमेल

एलयू के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉ. डीआर साहू कहते हैं कि जिस तरह से बच्चे और टीनएजर्स सोशल मीडिया और गेमिंग में इंडल्ज हो रहे हैं, वो सोसायटी से बिल्कुल कट ऑफ होते जा रहे हैं. हालांकि, इसमें एक बड़ा रीजन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी है. आज का टीन फैमिली डिनर या प्रोग्राम्स में भी सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखता है.

निभानी होगी जिम्मेदारी

एलयू की साइकोलॉजी प्रोफेसर डॉ. मानिनी श्रीवास्तव कहती हैं कि बच्चों की ग्रोथ और उनकी आदतों में पेरेंट्स का बड़ा रोल है. अगर पेरेंट्स बच्चों को फोन के बजाए टाइम दें तो आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं न तो बच्चा गेमिंग के लिए एडिक्ट होगा और न ही कोई खतरनाक कदम उठाएगा, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में पेरेंट्स वर्क-लाइफ बैलेंस बनाते-बनाते क्यों की तरफ ध्यान देना ही भूलते जा रहे हैं.

DAINIK JAGRAN

स्किट में इंटीग्रल, हिट द बज में लवि विजेता

लखनऊ : एमिटी ला स्कूल, एमिटी विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर में आयोजित दो दिवसीय 5वें लेक्स कार्निवाल-ज्यूरिस ट्रैक 2026" का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। इस कार्निवाल में देश भर के 200 से अधिक विधि छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में सहभागिता की। समापन सत्र में मुख्य अतिथि डा. राम मनोहर लोहिया नेशनल ला यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर डा. अपर्णा ने विजेता दलों को पुरस्कार और पदक देकर सम्मानित किया।

स्किट प्रतियोगिता में इंटीग्रल विश्वविद्यालय की टीम विजेता रही, जबकि "हिट द बज" प्रतियोगिता में लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। "नो योर रोल" में भातखंडे विश्वविद्यालय तथा लीगल मैक्सिम बी प्रतियोगिता में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी की टीमों ने प्रथम पुरस्कार अपने नाम किया। प्रति-कुलपति प्रो. (डा.) अनिल वशिष्ठ ने अतिथियों को स्मृति-चिह्न भेंट किया। वि

VOICE OF LUCKNOW

कॉलेजों के विभागों को रिसर्च सेंटर की दी जायेगी मान्यता

- लविवि में कुलपति प्रो. जेपी सैनी की अध्यक्षता में एडेड एवं राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों की अहम बैठक सम्पन्न

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जेपी सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें एडेड कॉलेजों एवं राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के बीच शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अनुसंधान संबंधी सहयोग को सुदृढ़ करना था।

बैठक में विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी, वित्त अधिकारी हिमानी चौधरी तथा प्रवेश समन्वयक प्रो. अनिल गौरव भी उपस्थित रहे। संचालन का दायित्व डॉ. अश्विनी कुमार मिश्रा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ ने निभाया।

बैठक में कुलपति ने प्रस्ताव रखा कि एडेड कॉलेजों एवं राजकीय महाविद्यालयों के प्रवेश विश्वविद्यालय की प्रक्रिया से जोड़े जाएं। विश्वविद्यालय परिसर में सीमित सीटों के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता। ऐसे छात्रों को एडेड कॉलेजों में अवसर दिया जाएगा। इस व्यवस्था में विश्वविद्यालय कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लेगा और कॉलेज अपने स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित करेंगे। कुलपति ने इस प्रक्रिया के चिंतन के लिए प्राचार्यों को 10 दिन का समय दिया है। वहीं, प्राचार्यों ने विश्वविद्यालय द्वारा कोई शुल्क न लेने के निर्णय की सराहना भी की।

साथ ही कुलपति ने घोषणा की कि महाविद्यालयों के विभागों को रिसर्च सेंटर के रूप में मान्यता दी जाएगी। इससे विभागों को विश्वविद्यालय से पूर्ण सहयोग मिलेगा और शोध कार्य को नई दिशा मिलेगी। शोध केंद्रों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति निरीक्षण करेगी।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्चतम स्वायत्तता के लिए तैयार किया जाएगा। शिक्षकों को कार्यशालाओं में आमंत्रित कर उन्हें जागरूक पाठ्यक्रम और छात्र-हितैषी शिक्षा पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कुलपति ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के बीच संवाद का माध्यम लगातार सक्रिय रहेगा। हर 6 महीने में कुलपति महाविद्यालयों के प्राचार्यों से बैठक करेंगे। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कई महाविद्यालयों में छात्र संख्या घट रही है। विशेषकर कन्या महाविद्यालयों में छात्राओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। सुझाव दिया गया कि ऐसे महाविद्यालयों को सह-शिक्षा में परिवर्तित किया जाए ताकि छात्राओं को अधिक अवसर मिल सके। कुलपति ने कहा कि शिक्षक स्वयं को अधिकारी न समझें, बल्कि छात्रों के बीच प्रेरक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएं क्योंकि उनका संवर्ग एक अलग संवर्ग है जो समाज को राह दिखाता है।

बैठक में उपस्थित सभी प्राचार्यों ने इस पहल का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय के साथ सतत सहयोग करते रहेंगे। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का संबंध कॉर्पोरेट स्टाइल में होगा, जहां समस्याओं का स्पष्ट समाधान विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। इस बैठक ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के बीच सहयोग की नई राह खोली है।

HT

Hindustan Times

LU MOVES TO INTEGRATE AIDED, STATE COLLEGE ADMISSIONS

HT Correspondent
letters@htdive.com

LUCKNOW: Admissions to aided colleges and state colleges must be integrated with the Lucknow University's admission process, Prof JP Saini, vice-chancellor, LU, put forward the proposal during a meeting with principals of aided and government colleges of the university on Tuesday.

"Due to limited seats on the university campus, a large number of students are unable to secure admission. Such students will be given opportunities in aided colleges. Under this arrangement, the university will not charge any additional fees, and the colleges will conduct the admission process on their own," said Saini.

He has given the principals 10 days to consider this process. He also announced that college departments will be recognised as research centres which will provide the departments with full support from the university and give research a new direction and a committee formed by the university will oversee the establishment of research centres.

The meeting also discussed the declining student numbers in many colleges. Girls' colleges in particular are experiencing a decline in the number of women students. It was suggested that such colleges be converted to co-education to provide more opportunities to women students.

The vice-chancellor said that teachers should not consider themselves authorities, but rather serve as motivators and guides for students.

Saini said that it is essential to increase the gross enrollment ratio in colleges. "Aided and government colleges will have a special responsibility for this, and colleges will need to make concerted efforts."

AMAR UJALA

बिना शुल्क केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ेंगे राजकीय व एडेड कॉलेज

माई सिटी रिपोर्टर

लखऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय और एडेड कॉलेज अब बिना किसी शुल्क के विश्वविद्यालय की केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ सकेंगे। कुलपति प्रो. जेपी सैनी ने मंगलवार को प्राचार्यों के साथ हुई बैठक में यह घोषणा की। इसके लिए उन्होंने सभी प्राचार्यों को 10 दिन का समय दिया है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए हर साल सीट के मुकाबले कई गुना अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। इसको देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने चार साल पहले केंद्रीकृत प्रवेश काउंसलिंग की व्यवस्था शुरू की। इसमें शामिल होने के लिए सभी महाविद्यालयों को 50 हजार रुपये प्रति पाठ्यक्रम शुल्क देना होता था।

साधन संपन्न निजी महाविद्यालय जहां इसमें बढ़-चढ़कर शामिल होते थे, वहीं राजकीय और अनुदानित महाविद्यालय वित्त के अभाव में केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाते थे। इसका नतीजा यह होता था कि लविवि की सीट भरने के बाद राजकीय और अनुदानित के बजाय निजी महाविद्यालयों की सीटों पर दाखिले होते थे। दाखिला लेने वाला विद्यार्थी आवेदन तो लविवि में दाखिले के लिए करता था, लेकिन ज्यादातर को विश्वविद्यालय की सीट भरने के बाद निजी महाविद्यालय जाना पड़ता था। ऐसे में राजकीय और अनुदानित कॉलेजों की सीट खाली रह जाती थीं।

दूसरी ओर दाखिला लेने के बाद विद्यार्थी को पता चलता था कि लखनऊ में राजकीय और अनुदानित कॉलेज में एडमिशन का मौका था, लेकिन जानकारी के अभाव में वे चूक गए। अब लविवि की प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रह जाने वाले विद्यार्थियों को एडेड और राजकीय महाविद्यालयों में अवसर मिल सकेगा। बैठक में विश्वविद्यालय की कुल सचिव डॉ. भावना मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी, वित्त अधिकारी हिमानी चौधरी, प्रवेश समन्वयक प्रो.अनित्य गौरव भी मौजूद रहे।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्राचार्यों के साथ हुई बैठक में दिया आश्वासन

सरकारी कॉलेजों में सीट खाली रहने की समस्या का होगा समाधान

महाविद्यालयीय विभागों को मिलेगी रिसर्च सेंटर की मान्यता

बैठक में कुलपति ने घोषणा की, योग्य और पात्र महाविद्यालयीय विभागों को रिसर्च सेंटर के रूप में मान्यता दी जाएगी। इससे शोध कार्य को बढ़ावा मिलेगा और विश्वविद्यालय स्तर से पूरा सहयोग मिलेगा।

■ **कन्या महाविद्यालयों को को-एड में बदलने का प्रस्ताव :** कुलपति ने कहा कि विशेषकर कन्या महाविद्यालयों में छात्राओं की घटती संख्या चिंताजनक है। समाधान के तौर पर कुछ महाविद्यालयों को को-एड (सह-शिक्षा) में बदलने का प्रस्ताव रखा।

■ **हर छह माह पर होगी कुलपति के साथ प्राचार्यों की बैठक :** कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के बीच संवाद निरंतर बना रहेगा। हर छह माह में प्राचार्यों के साथ बैठक होगी। कहा कि यदि महाविद्यालय दुखी रहेगा तो विश्वविद्यालय सुखी नहीं रह सकता।

■ **गुणवत्ता रैंकिंग बेहतर करने के लिए होगी कार्यशालाएं :** बैठक में यह भी तय हुआ कि लविवि की रैंकिंग सेल, महाविद्यालयों के नैक और एनआईआरएफ रैंकिंग की तैयारी के लिए संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित करेगी। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों का संबंध कॉर्पोरेट शैली में होगा, जहां समस्याओं का समाधान विश्वविद्यालय स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा।

NBT

LU की काउंसलिंग से कॉलेजों में भी मिलेगा दाखिला

जो कॉलेज सहमति देंगे उनके कॉलेजों को एलयू की एडमिशन प्रक्रिया में किया जाएगा शामिल, एलयू की सीटें भरने के बाद छात्रों को दिया जाएगा विकल्प

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय में आवेदन करने वाले छात्रों को अब कॉलेजों में भी दाखिले का विकल्प दिया जाएगा। विवि की ओर से इस बार एडमिशन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत एलयू की सीटें भरने के बाद अब जो भी छात्र रह जाएंगे उन्हें काउंसलिंग में विकल्प दिया जाएगा कि वह कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। खास बात ये है कि इसके लिए कॉलेजों को अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। मंगलवार को एलयू में ऐडेड व राजकीय कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक में वीसी प्रो. जेपी सैनी ने यह बात कही।

कॉलेजों को नहीं देना होगा अलग से कोई भी शुल्क

बैठक में वीसी ने कॉलेजों में दाखिले की संख्या घट रही है, जबकि एलयू में हर साल कई हजार छात्र दाखिले से वंचित हो जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वीसी ने कहा कि इसके लिए कॉलेजों पर न तो कोई भार डाला जाएगा न ही कॉलेजों को कोई प्रक्रिया बदलने के लिए कहा जाएगा। कॉलेज अपने स्तर से जैसे दाखिले की प्रक्रिया संचालित करते हैं वो कर सकते हैं। साथ में उन्हें एलयू की काउंसलिंग में शामिल होने का अतिरिक्त मौका दिया जाएगा। जो भी छात्र काउंसलिंग की बैठक में चयनित होंगे उन्हें कॉलेज दाखिले के लिए भेजा जाएगा बाकी फीस जमा करने से लेकर बाकी प्रक्रिया कॉलेज जैसे संचालित करते हैं कर सकेंगे।

हर छह महीने में बैठक, एनईपी के तहत काम

बैठक में कुलपति ने कहा कि अगर कॉलेज दुखी रहेंगे तो विश्वविद्यालय सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हर छह महीने पर कॉलेजों के साथ बैठक होगी ताकि संवाद बना रहे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उच्चतम स्वायत्तता के लिए तैयार किया जाएगा। शिक्षकों को कार्यशालाओं में आमंत्रित कर उन्हें नई शिक्षा पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कुलपति ने ये भी कहा कि शिक्षक स्वयं को अधिकारी न समझें, बल्कि छात्रों के बीच प्रेरक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाए। कक्षाओं का औचक निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे।

HINDUSTAN

विधि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा हुई

लखनऊ। एलयू के विधि संकाय में स्थापित विधिक सहायता केंद्र की ओर से राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत नोशन इंटरवेशन का आयोजन हुआ। केंद्राध्यक्ष डॉ. अभिषेक तिवारी ने बताया कि विधि संकाय के मूट कोर्ट हॉल तरुणिमा बाजपेई ने शक्ति संवाद : कानून अपनी दृष्टि से विषयक विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की मध्यस्था भूमिका नीलजय ने विधि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका के महत्व पर चर्चा की।

DAINIK JAGRAN

- लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, आरके मुकर्जी सभागार, समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, सुबह 10:30 बजे।

AMRIT VICHAR

- लखनऊ विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ समाज कार्य विभाग के अंतर्गत समर्पण दिवस के तहत दीनदयाल की जयंती पर परिचर्चा- 10:00 बजे से।